(ग) बस्तर क्षेत्र में कालाजार व्याप्त नहीं है । मलेरिया रोकथाम के लिए बस्तर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

1. रोगियों का पता लगाना और मलेरिया के रोगियों का उपचार करना ।

2. मलेरिया के संचरण की रोकथाम करने के लिए उपयुक्त कीटनाशकों से अंतरंग कीटनाशी छिड़काव करना ; और

3. मलेरिया रोधी उपायों में आदिवासी लोगों को शामिल करके उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए धन का आबंटन

3536. **श्री लक्खीराम अग्रवाल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए प्रतिमाह 50 रु. का मानदेय निर्धारित किया गया है जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने कम से कम 100 रुपए प्रतिमास देने के लिए प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने यह सिफ़ारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार को परिवार कल्याण कार्यक्रमों का शत-प्रतिशत खर्च वहन करना चाहिए, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश सरकार को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ): (च) और (ख) परिवार कल्याण स्कीमों के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य कार्यकर्ता का कोई पद नहीं है । तथापि, उपकेन्द्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड/स्वैच्छिक कार्यकर्ता को 50/– रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाता है ।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम इसे शुरू किये जाने (1951–52) से ही 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम है ।

(घ) मध्य प्रदेश को 1991-92 के दौरान (अब तक) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 4558.11 लाख रुपए की रकम का भुगतान किया गया है ।

Extension of C.G.H.S. facilities

3537. **SHRI RAMACHANDRAN PILLAI** : Will the Minister of HEALTH and FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Ichapur Ordnance Factories Mazdoor Union Goalpara PO Ichapur-Nawabgani 24-Parganas West Bengal have submitted a memorandum dated 30th January 1992 regarding extension of C.G.H.S. facilities to the retiredem ployees of Ordance factories in the said area where the C.G.H.S. facilities do not exist ;

(b) if so what steps Government have taken in this regard ; and